सरकार की प्राथमिकता है। गृह मंत्रालय ने निश्चित रूप से हमें कुछ निर्देश दिए थे, केवल 15-16 स्थानों को छोड़कर बाकी सभी जगह पर जो सैंक्शन था, वहां पर टावर्स लगा दिए गए हैं और वे radiate कर रहे हैं। अगर कोई विशेष क्षेत्र है, तो माननीय सदस्या से मैं आग्रह करूंगा कि वे उसके बारे में मुझे लिखित रूप में दे दें, तो मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या का भी समाधान हो जाए।

श्रीमती रेणुका चौधरीः मंत्री जी, समस्या यह है कि जब टावर सैंक्शन हो जाता है, तो उसको माओइस्ट्स उखाड़ देते हैं, तो दोबारा वहीं पर टावर लगाने के बारे में कहा जाता है कि अबकी बार आप रुकिए, आप ठहरिए पहले पूरा एरिया कवर करेंगे, फिर दोबारा से आपका टावर सैंक्शन होगा। इतनी देर में तो बड़ा नुकसान हो जाता है।

श्री मनोज सिन्हाः सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्या से यही अर्ज किया है कि अगर ऐसी कोई घटना आपके क्षेत्र में हुई है, तो कृपया उसकी सूचना दें, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा।

श्रीमती रेणुका चौधरीः धन्यवाद।

Quality of food service in Ahmedabad-Delhi Swarna Jayanti Rajdhani express train

*111. SHRI SHANKARBHAI N. VEGAD: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Railways have received complaints regarding bad quality food service by private catering agency in Ahmedabad-Delhi Swarna Jayanti Rajdhani Express train, if so, the details thereof;

(b) the action taken by Railways against the food contractor;

(c) whether it is a fact that the food contractor on this route is blacklisted; and

(d) if so, the authority which has taken the decision to give a further contract to him?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. 133 catering complaints have been reported on Train No. 12957-12958 (Ahmedabad-New Delhi Swarna Jayanti Rajdhani Express) during the period May, 2016 to February, 2017. A total fine of ₹ 9,55,000/- has been imposed and ₹ 8,30,000/- has already been recovered by the Railway during this period, against 104 complaints. Notice of termination has been served to the catering contractor of Train No. 12957-12958 in terms of the contract signed by him with Western Railway. Improvement of catering services is an on-going process. In its endeavour

to provide quality and hygienic food to the passengers, Railways have developed and operationalized an institutionalized mechanism for monitoring of quality and hygiene of catering services through regular inspections at various levels to address catering complaints. Further, a new Catering Policy 2017 has been announced and issued on February 27, 2017, wherein unbundling of catering services by Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), has been envisaged on a large scale by encouraging the entry of professional private catering companies, so as to improve the travelling experience for the common railway passenger too.

(c) No, Sir.

(d) Do not arise.

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार की जो खान-पान नीति 2017 में घोषित की गई है और अभी जो सहूलियत मिल रही है, उस नीति के कारण आने वाले दिनों में पैसेंजर्स को क्या इससे अच्छी फैसेलिटी मिल सकती है? अगर मिल सकती है, तो कैसी फैसिलिटी मिल सकती है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं?

श्री सुरेश प्रभुः सर, आज की जो खान-पान सेवा के बारे में नीति है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए 27 फरवरी, 2017 को हम लोगों ने एक नई नीति जारी की है। इसमें काफी आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं। इसमें एक बात यह है कि खाना बनाने वाला और खाने का वितरण, दोनों व्यवस्थाओं को पूरी मात्रा में हम लोगों ने अलग-अलग कर दिया है। खाना बनाने के लिए बेस किचन्स बनायी जाएंगी और पूरी मैकेनाइज्ड किचन आईआरसीटीसी की निगरानी में काम करेगी। उसका लाभ यह होगा कि जब खाने की क्वालिटी, जहां पर खाना बनता है, वहां पर ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर लोगों को जो खाना दिया जाता है, उसमें तो जरूर खराबी होगी। इसलिए इसमें सबसे पहले आमूल-चूल परिवर्तन होना जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि जो खाना लोगों को देंगे, उसके लिए हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी प्रोफेशनल एजेंसी का अभी टेंडर बन रहा है। उन सब को invite किया जाएगा और वे ही खाने को distribute करने का काम करेंगे। यह काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। साथ ही, जो static unit है, उसके बारे में हमारी सभी महिला सदस्याएं सुनकर खुश होंगी कि उसमें हमने महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण रखा है। जहां भी स्टाल्स दिए जाएंगे, वहां पर आरक्षित स्टालो में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्टाल्स हमने रिजर्व करने का फैसला कर लिया है। पार्लियामेंट ने अभी तक सांसदों के बारे में.. लेकिन हमने यह पहला फैसला कर दिया है।

श्री सभापतिः ठीक है।

श्री सुरेश प्रभुः साथ ही में, हम लोगों ने यह भी किया है कि जो static stall है, वह पहले लाइफलांग दिया जाता था, अब वह पांच साल से ज्यादा समय के लिए नहीं दिया जाएगा, अगर उसमें क्वालिटी नहीं है या उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसके ऊपर फौरन हम एक्शन ले पाएंगे। साथ ही, हमने बड़ी मात्रा में ई-केटरिंग की शुरुआत की है। आज आपको जो खाना चाहिए,

आपकी पसंद का खाना, आपकी सीट के ऊपर दिया जाता है, उसके लिए Food Accredited Bill है, लेकिन जो पुरानी नीति थी, उसके तहत हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई थीं। आज जिस तरह से लोगों को खाना दिया जाता है, उसके बारे में शिकायतों के लिए हमने हॉटलाइन establish की, जो भी चाहे, उस पर शिकायत कर सकता है। और भी शिकायतें हैं, उनके लिए ट्विटर हैंडल भी दिया है, लेकिन जो काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसकी शिकायत जरूर आएगी। इसके लिए हमने उसमें पूरी तरह से परिवर्तन करने का फैसला लिया है। मुझे यह कहने में आनंद हो रहा है कि उसको पूरी मातरा में कार्यरत करने की शुरुआत भी हुई है और जो पुरानी व्यवस्था है, उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं।

सर, माननीय सदस्य ने पहला जो क्वेश्चन पूछा था, वह एक स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में पूछा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यह जो ट्रेन है, जिसमें इस तरह की सुविधा लोगों को दी जा रही थी, जिसके बारे में बहुत शिकायतें थीं। अब इसको तो वेस्टर्न रेलवे डील करता है, रेलवे बोर्ड के पास शिकायतें जाती थीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन जब माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा तो मैंने उसमें देखा और यह बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत सारी शिकायतें आई थीं और मैंने जांच का आदेश दिया। सर, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जो अम्बुज होटल है, रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी काम करती थी, उसका कल हमने कांट्रेक्ट टर्मिनेट करने का नोटिस दिया है। उसके खिलाफ हम लोग एक्शन भी लेंगे और उसे हम लोग ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे, क्योंकि इसका हमें भी पता नहीं।

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि साउथ इंडिया से जो ट्रेनें आती हैं, लगभग 20 ट्रेनें आती हैं, वे ट्रेनें अहमदाबाद यार्ड में आकर 20 घंटे तक या 24 घंटे तक पड़ी रहती हैं। उन ट्रेनों को सौराष्ट्र तक बढ़ाया जाए और पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, राजकोट तक बढ़ाया जाए, इससे रेलवे को भी मुनाफा होगा और साउथ इंडिया से आने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। क्या भविष्य के लिए ऐसा कोई विचार सरकार के विचाराधीन है?

श्री सुरेश प्रभुः सर, यह प्रश्न हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, फिर भी यह एक सुझाव है, इसलिए हम इस सुझाव के बारे में जरूर सोचेंगे।

श्रीमती कहकशां परवीनः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि राजधानी एक्सप्रेस की बात हो रही है और खानपान की बात हो रही है। जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस है या फिर रांची राजधानी एक्सप्रेस है, इन सब राजधानियों से पहले AC First Class के लिए जो रसोई यान थे, कुछ दिन पहले वे सब हटा दिए गए हैं। अब केवल एक ही रसोई यान है और उससे ही सभी यात्रियों को खाना मुहैया कराया जाता है। जब वहां पर खाना बन जाता है, तो लोग वहां से खाना लाते हैं और अपनी-अपनी बोगियों में रखकर लोगों को खाना सर्वे करते हैं। AC First Class की यह स्थिति है कि शौचालय के बगल में जो जगह होती है, वहां से लोगों को खाना परोसा जाता है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस ट्रे में खाना परोसा जाता है, उस ट्रे में जो मैट लगाया जाता है, उसमें "स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत" की बात कही जाती है। जब इस तरह से खाना परोसा जाता है, तो खाने में भी करारियत होती है, लेकिन वे बरतन कहां धोते हैं? अगर

चम्मच वॉश बेसिन में गिर जाए, तो वही चम्मच हमें इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। हम तो वहां जाकर देखते नहीं हैं, लेकिन इससे अंदाजा लगाते हैं। आपका जो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना है, क्या वह इससे साकार होगा, मैं यह जानना चाहती हूं?

श्री सुरेश प्रभुः सर, माननीय सदस्या ने जो स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में बात कही है, तो मैं इस बारे में जानकारी लेकर ही आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे यही बात कह रहा था कि जो पुरानी व्यवस्था पुरानी नीति के तहत चल रही थी, उसको लेकर जो शिकायतें आ रही थीं, आप जो बात कह रही हैं, वह भी पुरानी व्यवस्था के तहत ही चल रही है। उसमें पूरी मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि जो खाना बनाने की व्यवस्था है, वह कहीं पर नहीं होगी और एक मैकेनाइज्ड लेवल पर खाना बनाया जाएगा। रसोई वहीं पर रहेगी और खाना बनने के बाद उसका मैकेनाइज्ड वितरण होगा और IRCTC उसके लिए जिम्मेदार बनाई गई है, ताकि उसकी जिम्मेदारी तय हो। कोई निजी कॉन्ट्रेक्टर उसमें काम नहीं कर पाएगा, लेकिन खाना बनने के बाद उसके distribution का जो काम है यानी खाना बनने के बाद रसोई से लोगों तक पहुंचाने का जो काम है, उसको करने के लिए जो प्रोफेशनल एजेंसीज़ हैं, जो hospitality का काम करती हैं, उनको दिया जाए। आपने जो डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के बारे में पूछा है, मैं उसको जरूर देखूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**... मैं उसको जरूर देखूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे सांसद भाई, बहन या कोई भी आदमी इस तरह का खाना खाएं, मैं इसको जरूर देखूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती कहकशां परवीनः सभापति महोदय ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः थैंक यू, आपका सवाल खत्म हो गया है।

डा. सत्यनारायण जटियाः माननीय सभापति जी, खाना और पानी और उस पर हो अच्छी मेहरबानी, तो हमारी सुधर जाए कहानी। मैं जानता हूं कि कुछ अच्छी शुरुआत करने के लिए जैसे नई दिल्ली, मुम्बई राजधानी एक्सप्रेस में जो खाना दिया जाता है, बहुत सलीके से और बहुत बेहतर खाना दिया जाता है, किन्तु जितनी शताब्दी एक्सप्रेस चलती हैं, जिनमें मैंने भी सफर किया है, वहां खाने की गुणवत्ता को मेंटेन करने के कोई उपाय नहीं हैं। जो आदमी इन ट्रेनों में सफर करता है और रेलें जब कभी लेट हो जाती हैं, तो उसको ट्रेनों में खाना, खाना ही पड़ता है। इसलिए खाना ऐसा होना चाहिए, जिसमें सभी का गुज़ारा हो जाए और वह खाना साफ-सुथरा भी हो। उसमें ज्यादा डिशेज़ हों, ऐसा जरूरी नहीं है, किन्तु जो भी मिले, वह अच्छा मिले।

श्री सभापतिः आपका सवाल क्या है?

डा. सत्यनारायण जटियाः मेरा सवाल यह है कि अच्छा खाना देने के लिए क्या उपाय करेंगे और खान-पान की सेवाएं रेलवे स्टेशन्स पर हों, ताकि लोगों को गर्म खाना मिले। इसके लिए LPG के बर्नर वगैरह, जो हमारे नागदा, रतलाम रेलमंडल में बंद कर दिए गए हैं, खाना अच्छा और गर्म करने की सुविधाओं को क्या अब शुरू करेंगे?

श्री सुरेश प्रभुः सर, यह बात बिल्कुल सही है कि लोगों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। लोगों को खाना गर्म भी मिलना चाहिए, ताकि passenger भी अपने दिमाग से गर्म न हो और अच्छी तरह से खाना खा सके, ऐसा करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। मैंने कहा

है कि इसके लिए बेस किचन बनाए जाएंगे। मैंने अपने रेलवे बोर्ड को इसके लिए आदेश भी दे दिया है। अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। आज मैंने कह दिया और कल से बात नहीं बन पाएगी, लेकिन हमारी यह कोशिश है कि कम से कम डेढ़ या दो घंटे के अंदर बेस किचन में खाना मिले। जब ट्रेन पास करेगी, तो गर्म खाना वहां से पिक-अप करके डिस्ट्रिब्यूट करके लोगों को मिलेगा।

सर, आज भी हवाई जहाज में जो खाना मिलता है, वह बहुत पहले पकाया जाता है और उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। हम ट्रेन में लोगों को बहुत ही अच्छा और फ्रैश खाना देने में कामयाब रहेंगे, इसके लिए जो नई नीति बनाई है, उसमें बेस किचन की भी सुविधा है। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है कि लोगों को एथनिक खाना मिले। यानी यदि जयराम रमेश जी चाहेंगे कि उन्हें मैसूर का खाना मिलना चाहिए, हमारी बहिन को आंध्र प्रदेश का खाना मिलना चाहिए, तो हमने इसके लिए एक नए प्रयास की जो शुरुआत की है, उसमें यह व्यवस्था है कि लोगों को ऐसा एथनिक खाना मिले। मैंने बजट स्पीच में इसकी शुरुआत के बारे में कहा था। आज मुझे यह कहने में खुशी है कि हमने ई-केटिंरग के तहत कोंकण में, वहां के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें बहुत सारी गरीब महिलाएँ हैं, वे जो खाना बना रही हैं, हम वह खाना वहां से लेकर लोगों को दे रहे हैं। इस पर लोगों का इतना अच्छा प्रतिसाद है कि हम चाहते हैं कि यह सुविधा केवल कुछ ही नहीं, बल्कि बहुत अधिक मात्रा में लोगों को मिले। हम नहीं चाहते कि वेजिटेरियन खाने में सिर्फ पनीर ही रहे। क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूं, लेकिन मैं भी पनीर को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें एडिशन हो। हमारे देश में खाने में इतनी विविधता है, इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों न उस विविधता का हमारी केटरिंग सर्विस में भी रिफ्लेक्शन हो और लोगों को अच्छा खाना मिले।

SHRI RIPUN BORA: Mr. Chairman, Sir, I have a specific question. The hon. Railway Minister just now praised the food quality at so many destinations. But, Sir, I wish to say something as far as Assam is concerned. Sir, I am a regular traveller in the Guwahati-bound Rajdhani Express. The food quality is very poor, bad and unhygienic. I fully agree with my colleagues that the food is stored just in front of the toilets.

My question to the hon. Minister is whether the Minister will make some provision either to launch a helpline or to form a special squad so that whenever we have a complaint and we raise the issue either on the helpline or with the special squad, immediate action can be taken.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I have already answered this point. We have already created a helpline. In addition to that, those who wish to communicate with us through social media, they can do that. But the issue you raised is essentially the reason, rationale and justification for changing the policy was exactly the same. Today, the type of food that is served through the private contractors is not up to the expectations of the people. Therefore, we are changing it completely. I fully appreciate it. There was need for changing the policy. This was also announced in my

previous Budget speech. We consulted a large number of people. You know, it is not very easy in the Government to change something. It has got so many stakeholders and so many people having interests in this. So, we have actually addressed this, and, we have changed the policy.

Implementation of food security schemes

*112. SHRI KIRANMAY NANDA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 15 per cent Indians do not get full meal daily;

(b) whether it is also a fact that the food security efforts made by Government have not achieved the desired results; and

(c) if so, the details of action taken by Government to review the implementation of food security schemes?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI RAMVILAS PASWAN): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) No, Sir. In order to provide food security to the people, the Government is implementing the National Food Security Act, 2013 (NFSA), which provides for coverage of 75% of the rural and 50% of the urban population, for receiving highly subsidized foodgrains. The Act is now being implemented in all the States/Union Territories (UTs), covering about 80 crore beneficiaries. Implementation of the Act is reviewed regularly with States/UTs.

SHRI KIRANMAY NANDA: Sir, as my first supplementary question to the hon. Minister, I would like to know as to how much foodgrain has been allocated and disbursed to various States against their respective demands.

SHRI C. R. CHAUDHARY: Mr. Chairman, Sir, in fact, the question is related to कि हमारे देश में कितने लोग भूख से पीड़ित हैं या उनको दो टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। आपने अभी पूछा है कि किस स्टेट को कितना फूडग्रेन भेजा जा रहा है, आपको उसके लिए स्टेटमेंट की एक पूरी लिस्ट दे दी जाएगी। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि NFSA लागू होने के बाद कोई भी ऐसा नहीं है, भारत की two-thirds population is covered under this NFSA. Sir, 75 per cent in rural areas, and, fifty per cent in urban areas are all getting highly subsidized meal.

श्री किरनमय नन्दाः मैंने आपका वह आन्सर देखा है। ...(**व्यवधान**)...